



वर्ष : 13 , अंक : 113, पृष्ठ : 08, नई दिल्ली बुधवार 08 नवंबर 2023, मूल्य : 1.50/-

मुख्य अपडेट

अखिल भारतीय साहित्य परिषद, महानगर इकाई, गाज़ियाबाद एवं देवप्रभा प्रकाशन का सम्मान

.... पेज 03

डायल-112 की लड़कियों को पुलिस ने खींच-खींचकर वैन में डाला

.... पेज 05

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त करने का फैसला रह हुआ: कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई

.... पेज 07

छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान खत्म

शाम 5 बजे तक 70.87 प्रतिशत मतदान; तीन जगह नक्सलियों से मुठभेड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक 70.87 प्रतिशत मतदान हो चुका था। वहीं मतदान के बीच नक्सलियों ने जमकर आतंक मचाया। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं। सुकमा में दो अलग-अलग आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। अभी मीनपा इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के



मुताबिक, 3 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा कांकेर में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक किसान घायल हुआ है। बीजापुर में कई नक्सलियों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद नक्सली

भाग निकले।

सबसे ज्यादा खैरागढ़ में 76.31 प्रतिशत, सबसे कम वोटिंग बीजापुर में 40.98 प्रतिशत

जिन 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। केवल एक राजनांदगांव सीट भाजपा के पास है। 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट भाजपा के पास थी, लेकिन नक्सली हमले में विधायक की मौत के बाद हुए उप चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे ही खैरागढ़ सीट जेसीसीजे के पास थी,

लेकिन उप चुनाव में इस पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। कवर्धा और मोहला-मानपुर सीट पर भी अभी कांग्रेस विधायक हैं।

233 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद

इन 20 सीटों पर 233 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हैं। इनके अलावा 198 पुरुष, 25 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे।



सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए एक सार्वजनिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया।

मिजोरम में शाम चार बजे तक 74.82 प्रतिशत मतदान हुआ

एजेंसी

आइजोल। मिजोरम में 40 सीटों वाले विधानसभा के चुनाव के लिए मंगलवार को शाम चार बजे तक 74.82 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव हुआ। हालांकि मतदान केंद्र शाम चार बजे तक बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन मतदान केंद्र बंद होने के समय के बाद



भी कई मतदान केंद्रों के अंदर मतदाताओं की कतारें लगी हुई थीं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच. लियाजेल्ला ने कहा

कि अंतिम मतदान 80 प्रतिशत से अधिक हो सकता है क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर मतदान अभी भी जारी है। लियाजेल्ला, मीडिया सेल के नोडल अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और राज्य भर के 1,276 मतदान केंद्रों में से किसी से भी कोई अग्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। मतदान प्रक्रिया सुबह सात बजे बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई।

मोदी ने डी.बी. चंद्रगौड़ा के निधन पर जताया शोक

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के वायोवृद्ध राजनीतिज्ञ और राज्य विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष दारादाहल्ली बायरेगौड़ा (डी.बी.) चंद्रगौड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “श्री डी.बी. चंद्रगौड़ा जी के निधन से बहुत दुः ख हुआ है। जनसेवा के प्रति निष्ठावान और एक सांसद, विधायक तथा कर्नाटक में मंत्री के रूप में उनके व्यापक अनुभव ने एक अमिट छाप छोड़ी है।

बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पास

बिहार में देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे जारी, यादव-भूमिहार सबसे गरीब, कायस्थ सबसे संपन्न



एजेंसी

पटना। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य में आरक्षण का दायरा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में मंगलवार को ही आरक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया था, इसके ढाई घंटे बाद ही कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। अब आरक्षण बिल को 9 नंबर को सदन के सदन के पटल रखा जाएगा। सदन से बिल पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। इससे पहले बिहार में मंगलवार को देश

का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16 प्रतिशत, सामान्य वर्ग में 25.09 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58 प्रतिशत, सुप्रीम कोर्ट के 42.93 प्रतिशत और एसटी 42.7 प्रतिशत गरीब परिवार हैं। सबसे ज्यादा गरीब यादव और भूमिहार हैं और सबसे संपन्न कायस्थ हैं।

सीएम ने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई

सर्वर्ण में हिन्दू-मुसलमान की 7 जातियां शामिल

बिहार सरकार ने जिन जातियों को सर्वर्णों में शामिल किया है, उसमें हिन्दू और मुसलमान धर्म की 7 जातियां हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32 प्रतिशत गरीब हैं। कायस्थ 13.83 प्रतिशत गरीब आबादी के साथ सबसे संपन्न हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के लोग सबसे गरीब हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जातीय गणना की आर्थिक रिपोर्ट की कांपी विधायकों को बांटी गई। 12 अक्टूबर को सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की थी। आबादी की शैक्षणिक स्थिति की बात करें तो 7 फीसदी लोग ग्रेजुएट हैं। इधर प्रवासी बिहारियों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महज 1.22 फीसदी आबादी ही राज्य से बाहर रहती है।

जाएगी। जमीन खरीदने के लिए 1 लाख दिया जाएगा। इस पर 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेंगे। अगर विशेष राज्य क दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही पूरा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र से हम लोग मिले थे, तब उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया गया कि आप अपने राज्य में करा लीजिए। इसके बाद निर्णय हुआ कि जनगणना केंद्र करेगा और हम लोग जातीय गणना करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस जाति की आबादी बढ़ा दिया और जाति नींव को नष्ट करना चाहती है। जब देश में जातीय जनगणना हुआ ही नहीं है। ये पूरा बोगस बात लोग बोल रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो केंद्र जातीय जनगणना करा लें।

दिल्ली-प्रदूषण : पांच राज्यों को पराली जलाने को रोकने का आदेश

प्रदूषण के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को आदेश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘जानलेवा’ प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने संबंधित सरकारों से कहा कि उसे या तो बलपूर्वक कार्रवाई करके या प्रोत्साहन के जरिए पराली जलाने से रोकना होगा।

पीठ ने पराली जलाने पर रोक के अमल के लिए स्थानीय थाना प्रमुख

को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव की निगरानी में निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, गोपाल शंकरनारायणन और न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह तथा अन्य को दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, पराली जलाना प्रदूषण का बड़ा हिस्सा है। इसे रोकना चाहिए। यह एक प्रमुख मुद्दा और प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। धान की खेती एक समस्या है। तुरंत कुछ

किया जाना चाहिए। यह फसल राज्य के जल स्तर को भी नष्ट कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से दूसरे राज्यों से अनाज की तस्करी हो रही है। शीर्ष अदालत ने कहा, हम



हरियाणा के 7 जिलों में 5वीं तक स्कूल बंद चंडीगढ़। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण को देख 7 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। मंगलवार को जींद और कैथल के बाद पानीपत व रोहतक में भी 5वीं क्लास यानी प्राइमरी स्कूल तक छुट्टियां कर दी गई हैं। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में नर्सरी से प्राइमरी तक स्कूल बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों के डीसी को शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में छुट्टी करने के अधिकार दिए थे। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं। इनमें करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल हैं। इनमें से गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक पानीपत और जींद में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। बाकी जिलों को लेकर भी जल्द फैसला हो सकता है।

मांगे

पटना में 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग

पटना। बिहार विधानसभा का घेराव करने निकली आंगनबाड़ी सेविकाओं को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सेविकाओं के साथ पहुंचे उनके परिवार के लोगों पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया है। घायलों को पुलिस ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया है। बिहार में अपनी मांगों को लेकर करीब 5 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों की 10 हजार सेविकाएं 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मानदेय की जगह वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को



लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं विधानसभा का घेराव करने निकली थीं। सेविकाओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मानदेय डबल कर देंगे। हमने कोरोना काल में मौत को सामने देखकर काम किया गया है। अभी

5,900 रुपए मिल रहे हैं। इससे परिवार नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है। प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज किया गया है। यह पूरी तरह से गलत है। अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5 हजार 950 सैलरी दी जाती है। वो 25 हजार रुपए की मांग कर रही हैं।

वहीं, आंगनबाड़ी सहायिका की सैलरी 2,700 है। वो 18 हजार की मांग कर रही हैं।

आज भी जारी रहेगा प्रदर्शन

आंगनबाड़ी सेविका संघ के महासचिव कुमार विदेश्वर सिंह ने विन्देश्वर सिंह कहा कि देर शाम धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। हालांकि, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो कल भी आंदोलन जारी रहेगा। सात घंटे धरना-प्रदर्शन करने के बाद डाक बंगला चौराहा खाली कर दिए हैं। महिला पुलिस की लाठी से मुजफ्फरपुर के औराई से आई

आंगनबाड़ी सेविका संघ की उपाध्यक्ष प्रतिमा देवी का सिर फट गया है। वो घायल हो गई हैं। बेहोश हैं। उनका काफी खून निकला है। इधर, एसएसपी राजीव मिश्रा का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की खुद की चलाई ईंट से ही वो घायल हुए हैं। हमने कोई बल प्रयोग नहीं किया है। विधानसभा के पास से पुलिस ने सेविकाओं को हटा दिया, लेकिन साढ़े 11 बजे से वो डाकबंगला चौराहे पर जुटी हुई हैं। इसके चलते स्टेशन और गांधी मैदान आने-जाने वाले रास्ते पर जाम लग गया है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। समझाने की कोशिश भी जारी है।

संपादकीय



जहरीली हवा में सांस लेने की बढ़ रही विवशता

अफसोस की बात यह भी है कि वायु प्रदूषण से जिस तरह खतरे पैदा होते हैं, उसके भुक्तभोगी आम लोग होते हैं, मगर जब तक सरकार कोई सख्त नियम नहीं लागू करती, तब तक अपनी ओर से लोग वैसा सुनिश्चित करने की कोशिश शायद नहीं करते। ऐसे समय में आपात स्थिति को छोड़ कर निजी वाहनों का सीमित प्रयोग करना और सार्वजनिक वाहनों से सफर करने को तरजीह देना क्यों संभव नहीं है ?

तमाम आशकाएं और अनुमान सामने होने के बावजूद दिल्ली की हवा ऐसी रह गई कि है जिसे बेहद घातक स्तर तक खतरनाक कहा जा सकता है। मुश्किल यह है चुकी ने कारगर स्थिति के पूरी तरह बिगड़ने तक सचित्र होती है, न आम लोग प्रदूषण के कारणों को दूर करने में सहयोग देना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले तीन-चार दिनों से स्थिति बिगड़ती चली जाने के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए सम-विषम व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। इसके तहत फिलहाल तेरह से बीस तक नंबर तल दिल्ली में यह पाबंदी लागू रहेगी। हवा में घुलते ज़रूर के अक्स को कम करने के लिए पिछले दिनों उड़ाए गए बड़े कदमों के ज़रूर में यह दूसरा फैसला है।

गौरतलब है कि दिल्ली की प्राथमिक स्कूलों को दस नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, राजधानी की दस समस्या के महेनजर ग्रैप-न की पार्वतीय पहलसे से ही लागू है। हर साल डंड की शुक्रास्त में हवा के घनीभूत होने के साथ ही पहले-5 और अन्य घातक सूक्ष्म कणों के अस्त से जनजीवन बाधित होने लगता है। मगर मुश्किल यह है कि कारण और परिणाम के बारे में लगभग सब साफ होने के बावजूद सरकार तब कोई बड़ा पैसला करती है, जब मामला हाथ से निकलने लगता है। सम-विषम व्यवस्था के बाद दिल्ली की सड़कों पर ढीढ़ने वाले वाहनों की संख्या में कमी आगी और उनकी वजह से हम में घुलने वाले प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है।

सवाल है कि प्रदूषण में खेतीपरी पर काबू पाने के मामले में अगर सम-
विषम सहित आयायों को इतना ही कारगर माना जाता है तो इन्हें समय रहते
चरणबद्ध तरीके से लागू क्यों नहीं किया जाता ? क्या ऐसा संभव नहीं है कि इससे
मौसम में प्रदूषण की आम तस्वीर के संकट में तब्दील होने से पहले हवा में
खतरनाक तत्त्व घोलने वाले कारकों पर लगाम लगाने के साथ-साथ आम
लोगों के बीच भी जागरूकता अधियां चलाया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि
इस समस्या से लड़ने में उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है ?

यों भी तापमान में कमी के साथ अगर हवा में ठहराव की स्थिति बनती है, तो धूल और धुआँ के अलावा अन्य तत्व मिल कर वायु प्रदूषण की समस्या को जटिल बना देते हैं। इसकी वजह से वायु को गुणवत्ता खराब हो जाती है। पिछले महीने के आखिरी दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में दिल्ली की तस्वीर बिगड़नी शुरू हुई थी और तब से यह कमोबेश 'बहुत खराब' की श्रेणी में ही है। अब सम-विषम व्यवस्था के अलावा प्रैप-4 लागू होने के बाद स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन जब तक इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक हर साल इसी तरह तात्कालिक उपायों के जरिए संकट को संभालने की कोशिश करना पड़ेगी। अफसोस की बात यह भी है कि वायु प्रदूषण से जिस तरह खतरे पैदा होते हैं, उसके भुक्तभोगी आम लोग अपनी हैं, मगर जब तक सरकार कोई सख्त नियम नहीं लागू करती, तब तक अनेक और से लोग वैसा सुनिश्चित करने की कोशिश करना ही करते हैं। ऐसे समय में आपात स्थिति को छोड़ कर निजी तहजीब का सीमित प्रयोग करना और सार्वजनिक वाहनों से सफर करने की वजहों को संभव नहीं है? फिलहाल दिल्ली के हालात जैसे दिख रहे हैं, उसमें सरकार को प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, पर इसे संभालने में आम लोगों को भी अपना दायित्व समझना होगा।

कनाडा और भारत के बीच विवाद बेबुनियाद

कानडा में सिख समुदाय के लोगों की अच्छी-खासी तादाद है और वहां की राजनीति में उनकी दखल है। इसलिए वहां की सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई भी की कड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचती है। यही वजह है कि वहां खालिस्तान समर्थक संगठन मजबूत होते गए और वहीं से भारत में अलगाववादी गतिविधियां संचालित करते रहे। भारत ने अनेक बार ऐसे उपद्रवियों के बारे में कार्रवाई की अपील की, जो कानडा में रह कर भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। उनमें कई लोगों को दहशतवादी की सूची में डाला गया था। मगर कानडा की तरफ से उन अपीलों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। निज्जर भी उन्हीं सूचीबद्ध दहशतवादी में शामिल था। खालिस्तानी अलगाववादी हर्दीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अभी तक कानडा और भारत के बीच तनाव समझ नहीं हुआ है। कानडा में भारत के उच्चायुक्त ने निम्न पूछा है कि इस मामले से जुड़े सबूत कहाँ हैं, जांच की रपट कहाँ है? कानडा की तरफ से यह आरोप लगाया जाने के बाद से ही कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है, भारत सरकार इसके सबूत मांग रही है। मगर कानडा सरकार बिना किसी सबूत के लगातार कहती रही है कि भारत इस मामले की जांच में सहयोग बना। इस तनानी के चलते भारत ने कानडा निगरांकों को वीजा देना बंद कर दिया और कानडा में अपने राजनयिकों की संख्या कम करनी शुरू कर दी। कानडा ने भारत से अपने राजनयिक वापस बुला लिए। इस तरह कानडा में काम कर रहे या पढ़ाई करने गए भारतीय नागरिकों में नाकद बाका का वातावरण बना। कानडा में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि इस तरह बिना किसी पुष्टा सबूत के आरोप लगा देने की वजह से बेवजह दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हुए। हालांकि भारत हर वर्ष प्रयास करता रहा है कि कानडा के साथ रिश्तों को किसी भी रूप में बिगड़ना न दिया जाए। दहअसल, कानडा में सिख समुदाय के लोगों की अच्छी-खासी तादाद है और वहां की राजनीति में उनकी दखल है। इसलिए वहां की सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचती है। यही वजह है कि वहां खालिस्तान समर्थक संगठन मजबूत होते गए और वहीं से भारत में अलगाववादी गतिविधियां संचालित करने लगे। भारत ने अनेक बार ऐसे उपद्रवियों के बारे में कार्रवाई की अपील की, जो कानडा में रह कर भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। उनमें कई लोगों को दहशतवादी की सूची में डाला गया था। मगर कानडा की तरफ से उन अपीलों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। निज्जर भी उन्हीं सूचीबद्ध दहशतवादी में शामिल था। संदिग्ध स्थितियों में उसकी हत्या हो गई थी। यह कानडा सरकार के लिए जांच का विषय होना चाहिए कि निज्जर के हत्यारों का पता लगाए, मगर उसने जांच में कोई पुष्टा आधार जुटाए बिना बहुत आसानी से आरोप लगा दिया। कि इसमें भारतीय एजेंसी का हाथ है। इस तरह बेबूत वहां दह रिसे सिख समुदाय के लोग कुछ संतुष्टी हो जाएं, पर भारत के साथ रिश्तों में जो खटास आई है, उसे सुधरने में वक्त लगेगा। दो देशों के बीच रिश्ते आपसी विश्वास पर टिके होते हैं। इस तरह किसी समुदाय को संतुष्ट करने या उस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों की संरक्षण देकर नहीं टिके सक्ते। भारत के कानडा से बहुत पुराने संबंध हैं और वह अच्छी तरह जानता है कि भारत किस तरह खालिस्तानी अलगाववाद की समस्या से निपटने का प्रयास कर रहा है। जैसे अलगाववाद की आग वर्षों पहले शांत हो चुकी थी, उसे अगर कानडा में बैठे कुछ लोग सुलगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मित्र देश होने के नाते वहां की सरकार से अपेक्षा की जाती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर अनेक मौकों पर देखा गया कि खालिस्तान समर्थकों ने कानडा में विरोध प्रदर्शन किए, भारतीय राजनयिकों को परेशान करने की कोशिश की, भारतीय उच्चायुक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी, मगर वहां की सरकार शिथिल ही नजर आई। इस तरह बेवृत्तियद आरोप लगा कर कानडा ने खुद बेवजह भारत के साथ रिश्तों में दरार डाली है।



अशोक मधुप

वरिष्ठ पत्रकार

ये यक्ष प्रश्न दुनिया में गूँजन लगा है कि हमारा और ईसाइयत दुनिया कैसे रूके ? दुनिया चाहती है कि युद्ध रुके, शांति हो। इस युद्ध में हो रहे मानवता का विनाश बंद हो। पर प्रश्न है कि हो कैसे ? इन दोषाल मानने को तैयार है न हमारा इस देशों की जंग में गाजापट्टी का आम नागरिक बच्चे और औरतें मर रही हैं। प्यायल और बीमार को इलाज नहीं मिल रहा। गाजापट्टी में हुआ विकास बड़े- बड़े भवन, पारिवारिक केंद्र अस्पताल खंडहर में तबदील होते जा रहे हैं।

हमास ने सात अक्टूबर को
इज़राइल में हमला करके

इज्राइल के साथ-साथ क्षेत्र में चल रहे सामान्यीकरण और शांति के प्रयासों को बंद कर दिया। इसाइल पर हमान में औचक हमला कर सबको चौंका दिया। किया इस हमले में 20 मिनेट में पांच हजार के असापास रिफ्ट दागे गए। इतना ही नहीं यह इस्राइल का सुरक्षा घेरा और दीवार तोड़कर अपनी सुरक्षा और मारक क्षमता के लिए विख्यात इस्राइल में घुस गए। उन्होंने इस्राइल में भारी तबाही मचाई। इस हमले में इस्राइल के एक हजार से ज्यादा

नागरिक मारे गए। तीन हजार के आसपास घायल हुए हैं। सूचनाओं के कि 250 के आसपास महिला और बच्चों सहित इश्राइल के नागरिकों का अपहरण कर लिया हमसा के आतंकियों ने महिलाओं का निवस्त्र कर उनके सम्मान को तार-तार करने की ओर कदम नहीं छोड़ी। हमसा ने सड़कों पर महिलाओं के नग्न शव घुमाए गए थे और बच्चों को काटकर, जलाकर या अन्य क्रूर तरीकों से मार डाला गया था। इसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है।

इसाइल को सुखाया व्यर्थया, सेना और गुप्तचर व्यवस्था भी दूनिया में विख्यात है। इस सबके बावजूद वहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसाइल के पास दुनिया का अधुनिकतम सुखा, प्रसूतक और विश्व विख्यात सूत्रांतर है। फिर भी वह इस हमले के सामने विफल होकर रह गया। इससे भी महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि इसाइल को सैन्य अजेयता है। प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इससे इजराइल बौखाला हुआ है। वह गुप्ते में बुरी तरह तिलमिला रहा है। परिणाम स्वयं उसका इरादा हमारा को खत्म कर देने का है। एक माह से

चालू युद्ध में वह गाँजा पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। उसका इरादा हमसा को पूरी तरह खत्म कर देने का है। इस्राइल गाँजा पर बड़े पैमाने पर हमले का सहारा ले रहा है ताकि वह उस प्रतिरोध को बहाल करने की कोशिश कर सके जो उसे कभी मिला था, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि अगर गाँजा को नष्ट कर दिया जाता है और फिर से कब्जा कर लिया जाता है तो भी वह इसे पूरा कर पाएगा।

दरअस्ल युद्ध हमास और
इस्त्राइल के बीच है हमास फ़लस्तीन
का इस्लामिक चरमपंथी समूह है, जो
गाज़ा पट्टी से संचालित होता है। 2007
में गाज़ा पर नियंत्रण के बाद हमास के



विद्रोहियों ने इसराइल को बर्बाद करने का कसम खाई थी। तब से लेकर हालिया हमले तक ये चरमपंथी संगठन इसराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़ चुका है। दूसरा पक्ष इसराइल है। हमारा और इसराइल के युद्ध में गाजापट्टी का आम नागरिक बच्चे पिस रहे हैं, इसका युद्ध से कोई बास्ता नहीं। युद्ध से कोई लेना - देना नहीं। हमारा इसी गाजापट्टी नागरिकों बीच छिपे बैठ है इसराइल की पेरशानी का। कि वह हमला लड़कों और आम नागरिक में भेद कैसे करे ? उसने गाजापट्टी दिनां आम नागरिक से पिछले दिनों अपील भी की कि वह गाजा छोड़ जाएं। काफी चले गए , किंतु अब भी बड़ी संख्या में गाजा में रहने को मजबूर हैं। आरोप है कि हमारा उन्हें नहीं जाने दे रहा। वह आम नागरिक की आड़ लेकर बचना चाह रहा है।

दुनिया चाहती है कि यह विनाशकारी युद्ध रुके इस्राइल पर दबाव भी है, किंतु सात अक्टूबर का औचक और बड़े पैमाने पर हुए हमले को इस्राइल भुलाने को तैयार नहीं। वह हमला को खत्म करके ही रुकने की बात कर रहा है। उधर इसके 250 के आसपास बंदी भी अभी रिहा नहीं

हुए। उस पर मानसिक दबाव है कि अपने इन बंदियों को सुरक्षित रूप से छोड़ाए।

इसी दौरान फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमस के प्रवक्ता गाजी हमद ने दावा किया है कि हमस सात अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमलों को बार-बार दोहराएगा। बता दें कि, इस दिन हमस ने भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से यहूदी राज्य में एक आश्चर्यजनक घुसपैठ शुरू की थी। इसी बीच 24 अक्टूबर को लेबनानी टीवी चैनल एलबीसी के सातवा एक साक्षात्कार में, हमस के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा कि, %हमें पूरी ताकत के साथ यह कहने में कोई शर्म नहीं है। हमें इजराइल को सबक सिखाना होगा और हम ऐसा बार-बार करेंगे। गाजी हमद ने कहा कि इजराइल पर ऐसा देश है जिसका हमारी भूमि पर कोई स्थान नहीं है। और फिलिस्तीनी कब्जे के शिकार है। उन्होंने कब्जा समाप्त करने का भी आह्वान किया।

उधर इसराइल के प्रधानमंत्री
बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि
जंग खत्म होने के बाद अनिश्चित काल
के लिए गज़ा पट्टी की पूरी सुरक्षा की
जिम्मेदारी इसराइल के पास
होगी। अमेरिकी चैनल एबीसी न्यूज को

दिए एक इंटरव्यू में ये कहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने हमारा के कब्जे से संबंधकों को छुड़ाए जाने तक युद्ध रोकेने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया उन्होंने कहा, जहां तक समझ-समझ पर छोटे-छोटे विवादों की बात है - एक घंटा या दो घंटे रुकना - हमने पहले ही ऐसा कर चुके हैं। मेरा मान है कि हम परिस्थितियों को देखेंगे, ताकि सामान, मानवीय मदद अंदर आ सके। अमेरिका, फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश इस संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकेने (पॉज) की अपील कर रहे हैं। डायर इसराइली सरकार में मंत्री एमिचाइ एलियाहू ने हमारा के खलिफा 'गुजा पट्टी में परमाणु हथियार को इस्तेमाल' की बात की है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसका खंडन किया है, किंतु सरकार के एक मंत्री के बयान से स्पष्ट हो जाताहै कि इस्राइल इस समस्या से निपटने के लिए किसी भी सीमातक जा सकता है।

हमामें के बारे में जानकारी रखने वाले मातेन हैं कि सात अक्टूबर को जब हमारा नें हमला किया तो उसकी प्लानिंग नें सबको हैरान कर दिया । सात अक्टूबर को किए गए हमले की प्लानिंग से पता चलता है कि हमारा लक्ष्य अवधि के लिए जॉन लड़ने की तैयारी करके बैठा है । जंग शुरू होने से पहले हमामें के पास 40 हजार लड़कें बताए जा रहे थे । इजराइल की बमबारी में नौ हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है । इजराइल के पास अभी इस खवाल का जवाब नहीं है कि इनमें से कितने हमामें के लड़कें हैं और कितने आम लोग । इजराइल से ज्यादा मुताबिक वात हमामें के 50 से ज्यादा टोप कमांडो को खत्म कर चुकी है । जंग से पहले हमामें के पास 15 हजार रॉकेट्स का जखीरा था । इसमें 8100 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल दगो जा चुके हैं । अब भी सात हजार रॉकेट्स बचे हैं ।

2008 की जंग के वक्त हमारा सेना के अधिकतम सीमा 40 किमी (25 मील) थी, लेकिन 2011 तक यह बढ़कर 230 किमी हो चुकी है। गाजा में 80 फीट की गहराई में बनी सुरंगों के हमला के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। हमारा का प्लान था कि वो इजराइली सैनिकों को सुरंगों के जरिए घेर कर मारेंगे, ताकि इजराइल परेशान होकर बल सीजफायर का ऐलान करे। इजराइल ने दावा किया है कि वो 100 ऐसी सुरंगों को तबाह कर चुका है। चार नवंबर को इजराइली सेना के प्रबन्तका डेनियल हागरी ने दावा किया कि अब तक की जंग में गाजा अब दो हिस्सों में बंट चुका है। उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा। उत्तरी गाजा में हमें हमारा का सफाया कर रहे हैं और दक्षिण में चायलों की मदद। अगर हमें मदद मिलेगी तो हमें गाजा को लड़ना है कि दक्षिण में भी कोई हमला लड़ना है तो उसे भी मार गिराया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि जंग के 30 दिन पूरे होते-होते इजराइली सेना ने गाजा के दो टुकड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हमने भर की इस जंग ने फिलिस्तीन के नक्शे के अलावा हमारा की ताकत और मुस्लिम देशों की सियासत को बदलकर रख दिया है। गाजा की हथियारों की सप्लाई ईरान और लीबिया से होती है। इसाइल काफ़्रायस इस आपूर्ति और हमारा की आर्थिक मदद रोकने का होगा ताकि वह जल्दी हथियार डाल दे।

हमारा को तैयारी को देखते हुए लगता है कि वह जल्दी हार नहीं मानेगा। उसने हमला बहुत सोच समझ कर किया होगा। उसने हमले से पूर्व उसके परिणाम पर गंभीरता के साथ सोचा होगा। जैसे उसका हमला चौकाने वाला था, हो सकता है कि हमले के बाद इस्त्राइल से निपटने की तैयारी भी चौकाने वाली हों। ऐसे में कुछ कितना लंबा चलेगा, यह नहीं कहा जा सकता।

स्वाधीनता के संघर्ष, स्वाभिमान से उपजी भारत की एकता, अखंडता

ग्रीकन आठ सौ से हजार वर्षों की
स्वतंत्रता के बाद अनेक जीवन का
बलिदान देने और विभिन्न संघर्षों के
बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस
संघर्ष से प्राप्त स्वतंत्रता को हमें देश
की एकता, अखंडता एवं सामाजिक
समस्याओं की शक्ति से चिरकाल तक
स्थायी रूप से बनाए रखना है अब
कभी स्वतंत्रता पर खतरा ना आए यद्यपि
हमारे देश के दिग्दर्शकों को अपनी
कमरे जिजीविषा से बनाए रखना
होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद
हमारी एकता, अखंडता एवं
एकरूपता मजबूत हुई है, पर कतिपय
राजनैतिक मसूवों के कारण आज हम
साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता
और अलग-अलग भाषाओं के
संघर्ष से गुजर रहे हैं। हम आज मंदिर
, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के विवादों
को लेकर विवाद प्रस्तुत हो जाते हैं

फाँबी, हिंदी, अँग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तेलगु, और कभी असमी भाषा के अस्मजसंग में फस कर एक दूसरे का विरोध जताना शुरू कर देते हैं। मूलतः हमें राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता के द्वित्रेष, ईर्ष्या, जलान और सीमा तथा भाषाई विवाद से परे हटकर देश में अखंडता, सांप्रदायिक सद्भावना का एक शुद्ध वातावरण समाज में तैयार करना होगा, जिसके फलस्वरूप हम विकास की मुख्यधारा में अपना स्विकृत योगदान राष्ट्र के प्रति दे सकें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि भारत संपूर्ण विश्व में एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जहाँ मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों का एक एकात्मक सह अस्तित्व कायम है।

वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद शांति सद्भावना एवं किसी भी राष्ट्र की अखंडता एकता एकरूपता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवादी कभी अमेरिका और कभी भारत के दिल्ली, मुंबई और अनेक प्रदेशों को अपना निशाना बनाकर आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं और आतंकवाद ने कई राज्यों में अपार जहाजित तथा संपत्ति की क्षति पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त अलगाववादियों ने भी राष्ट्रीय एकता अखंडता को भंग करने का पुरजोर प्रयास किया है। राजनीतिक पार्टियों के संसुओं तथा उनका महत्वाकांक्षाओं के कारण भी अलग-अलग जातियों संप्रदाय तथा पूजा के पवित्र स्थानों को लेकर समाज को अलग करने का

बीजराजोपनिषद् की किया है। राजनीतिक पार्टियों के चंद राजनेता वोट बैंक काटने के लिए कभी अल्पसंख्यकों में अलगाव के बीज बोलेने का प्रयास करते हैं।

कभी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्गों को देश की मुख्यधारा से बहकाने का प्रयास करते हैं, और कभी किसी विशेष जाति प्रांत या भाषा के हकदार बन कर देश की एकता, अखंडता को खंडित करने का पुरजोर प्रयास करते हैं।

यह अत्यंत निंदनीय एवं चिंतनीय सामाजिक पहलू है, जिस संदर्भ में हमें गहन विचार करने की आवश्यकता भी है। सामाजिक स्तर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य वर्ग सुचारु रूप से भाई-बंधू अखंड विश्वास रखते हैं एवं सामान्य जीवन करने में विश्वास रखते हैं।

चुनावी समर के बीच महादेव एप के मुद्दे पर सियासी धमासान



राज्य सरकारों को आईटी अधिनियम के 69 ए के तहत वेबसाइट,एप को बंद करने का सिफारिश का अधिकार को जनता ने रेखांकित करना जरूरी

भारत के युवाओं को विभिन्न अवैध सट्टेबाजी कारोबारों, गेमिंग जुआ से बचाने जीएसटी रूपी स्पीड ब्रेकर से कहीं अधिक अवैध घोषित करना जरूरी - एडवोकेट किशन समुखदास भावनानी गोंदिया

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों की चूँक ग्राम सेवक से लेकर पंचायत समिति और विधान सभा से लेकर संसद तक सीधे जनता चुनती है। इसलिए इस सार्वजनिक जीवन वाले पदों के लिए प्रत्याशी को साफ सुथरा होना अति आवश्यक है, इसलिए हर्ष पक्ष विपक्ष दोनों स्तर पर अपन-

प्रतियोगी के भूतपूर्व, वर्तमान जीवन के हर पहलू को गहराई से जानें और परखते हैं। या किसी भी अवसर पर विवादास्पद मामलों में उसकी थोड़ी सी भी सल्लंत्ता नजर आए तो दिल का लाल और राय का पहाड़ बनाने से जरा सा भी नहीं चूकते और मुद्दे को नपक लेते हैं ऐसा अमेरिकी भारतसहित अनेकों देशों में रहने को पसंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति उसके बेटों पूर्व भारतीय उसके परिवार सहित अनेक मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुंजे हैं। वर्तमान समय में ऐसा ही एक मामला एक राज्य के तथ्यांक के महादेव अप के मुद्दे पर चुनावी समर के बीच महादेव अप के मुद्दे पर सियासी प्रभावमान मचा हुआ है। जहां विपक्षी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए राज्य के सीएम को घेर रही है, तो वहीं सीएम अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यहां तक कि पीएम जब शनिवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने घेरते हुए कहा कि सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। दरअसल, महादेव बुक ऐप ईंडी की रछार पर है। ऐप सुझावों के लिए ऑनलाइन पोस्ट में उपलब्ध कराता है। इसके प्रमोटर रायपुर में रहने वाले हैं, और दोनों के दुबई में होने की आशंका है। दोनों वन, से ऐप को चलाते हैं। इसे भारत में बैन कर दिया गया है। ईंडी एजेंसी ने कुछ

महीनों पहले एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कथित तौर पर सीएम के राजनीतिक सलाहकार के साथ संबंध को आशंका है कि अपनी अवैध गतिविधियों को नजर अंदाज करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों, राजनियोतों और अन्य लोगों को रिवर में सैकड़ों करोड़ रुपये गुलाबी के भ्रष्टाचार को बहो आ रही है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों पर बताया जा रहा है। मामले को ईडी ने हाथ में ले लिया है और इसके तहत दुबई तक पहुंच गए हैं जिसे रेखांकित करना जरूरी है। मेरा मानना है कि अभी हाल ही में जीएसटी कार्डसिल को 51वीं बैकड में ऑनलाइन गेमिंग घुड़दौड़, क्लबों में दम पर 28 प्रतिशत जीएसटी और फिर उसको भारत सरकार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसलिए हालांकि अबंध धंधों को जीएसटी वैध नहीं बनाता फिर भी बैकडडोर तो उसे आखिर समर्थन मिल रहा जाता है, इसलिए जर्नलि और इसकी सहलग्नता से युवाओं के बढ़ते आलसहवा मामलों को देखते हुए अब इस तरह की गेमिंग और एप्स को पूरी तरह से बंद किया जाना सम्यक को मुरी है। चूंकि अभी सिर्फ 22 एप्स पर बैन लगाई गई है जबकि इसके पहले भी 100 से अधिक पर बैन लगा है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध

नानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि भारत में युवाओं को विभिन्न अवैध स्ट्रेटबाजी कारोबार, गैमिंग, जुआ से बचाने जीएसटी रूपी स्पीड ब्रेकर से कहीं अधिक इनको अवैध घोषित करक़रु है।

जरूरी है।

साथियों बात अगर हम एक राज्य में ठीक चुनावी समर में ऐप पर बंदर्ज करी करें तो, चुनाव से ठीक पहले सिपासी बंदर्ज खड़ा हो गया है। महादेव ऐप को विपक्षी पार्टी ने चुनाव को मुहा बनाया है। इस मामले में सिधे-सिधेमुखझंमती जना सामाने आने के बाद तो पार्टी आक्रमक है। खुद पीएम ने तीखा हमला बोले हुए, कदाकि साधधारी पार्टी की सरकराने यहाँ की जनाता विश्वास तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। हालांकि, सीएम ने इन आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है। दंडअसल, केंद्र सरकार ने महादेव बेंटींग ऐप समेत अवैध स्ट्रेटबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइटों को प्रतिबन्ध करने का आदेश जारी किया है। आईटी मंत्रालय ने अवैधस्ट्रेटबाजी ऐप सिर्फिकेट के हिलाफ चल रही जांच के आदेश दिए हैं। आखिर क्या है महादेव ऐप और क्यों आया छत्तीसगढ़ में भूखाल। कैसे जुड़ा सीएम का नाम यह भूखाल वाले प्रश्न हैं। सीएम ने तज खसते हुए ऑनलाइन पर पर जारी

सयसी घमासान के बीच कहा कि हमारे खिलाफ साजिश रही जा रही है। विपक्षी आंदोलन प्रचलन निदेशालय (ईडी) महादेव ऐप के मालिकों को बचा रही है। अगर इन्हें नहीं कार्रवाई करनी है तो आरोपितों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ये पार्टी ईडी को हथियार बनाकर विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करता रही है। मैं पार्टी का दूक कि इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ और ना ही कभी वैसे मुलाकात हुई है जैसा कि दावे किया जा रहा है। मुझे बदनाम करने के लिए वो पार्टी ऐसा काम कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता ही विरोधी पार्टी को करारा जवाब देगी। आरोपी का कि पूरे देश में ऑनलाइन सबूतों की बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ इस राज्य में ही क्यों किया जा रहा है। क्योंकि यहा चुनाव है। चुनाव खत्म होने तक यह घुमावदार जारी रहेगा उसे खनीय है कि गिरफ्तार आरोपी से कड़ी पूछताछ और उसके जवाब से जल्द को हाथ से कई चींकां को बांदे खुलासे हुं ईमेल के मुताबिक, महादेव ऐप के प्रमोटर ने अब तक करीब 508 करोड़ रुपये दिए हैं। हालांकि एजेंसी नहीं जांच कि पैसे दिए गए या नहीं, इसकी कता चल रही है। इस मामले के खुलासे होने के बाद सीएम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि चुनाव के दौरान इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। किसी को

कुड़वाकर मैं पीएम का नाम कहवा दूँ तो क्या पीएम से एजेंसी पूछाऊँ करोगी। मैं तो क्या नाम लेना बहुत आसान है। साबित करना उतना ही मुश्किल काम है। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। इंडी ने यूएई से आप शख्स पार्श्वस्थ जकास है इंडी के पास सुखिय सूचना है। इस राज्य में 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के महानज महदेवद एप के प्रमोटर्स को आरो से खंडी माता में नकदी ले जाई जा रही है। ये ऐसी सत्तारूढ़ के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए एक कैश क्रूरियर को रायपुर से पकड़ा था। जॉन एचेंस ने दावा किया कि एंजेंट को ऐप प्रमोटर्स ने यूएई से भेजा था। इंडी ने 5.39 करोड़ रुपये की नकद राशि उनका कार से बरामद की। जज अरुणजी कार पर आरोपी ने स्वीकार किया है कि महदेव ऐप के प्रमोटर्स ने राज में आगामी चुनाव खर्चों के लिए आरो राजनेता को देने की व्यवस्था की गई थी।

इंडी ने महदेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनमें 15.59 करोड़ रुपये की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। इंडी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपअसल, महदेव एक ऐप एक ऑनलाइन स्ट्रेडबाजी क्लेफ्टफॉर्म है।



